



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)



प्राधिकार द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, बृद्धधार, मार्च 31, 1993/चैत्र 10, 1915

No. 124] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1993/CHAITRA 10, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे ऐसे यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि कंपनी और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिकृतना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा.का.नि. 249(अ).—राष्ट्रपति, द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं.आ. 152”

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1993

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विवार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, प्रथमतः—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1993 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के विवरण के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के विवरण के लिए लागू होता है।

3.(1) अनुच्छद 275 के खंड (1) के उपबंध के अनुसार, 1 अप्रैल, 1992 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदानों के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (11) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, जो उन स्तम्भों में उल्लिखित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने और "विशेष समस्याओं" के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूँजी की प्रकृति के बद्य के लिए हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

सारणी

राज्य	पुलिस	शिक्षा	जल	जनजाति	स्वास्थ्य	न्यूट्रिकल	जिला और खजाना और प्रशिक्षण	विशेष		
							राजस्व लेखा	समस्याएं		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(रुपए लाखों में)										
चांग्री प्रदेश	—	—	—	1.61	—	4.26	—	2.02	—	0.31
झासम	—	35.43	—	—	—	8.80	—	—	(—) 6.38	—
बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.68
हिमाचल प्रदेश	2.14	—	1.34	—	—	0.98	—	—	—	21.98
केरल	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	526.50
उड़ीसा	—	—	—	3.33	—	—	—	—	—	—
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217.91
द्वितीय	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—
बिहुरा	—	—	—	—	—	(—) 0.42	0.42	—	—	—
परिवासी दंगाल	—	476.15	194.66	—	—	—	—	—	—	—

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ, ऊपर विनिर्दिष्ट और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च के जारी :

परन्तु यह ऊपर कि किसी प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान को रकम 1 अप्रैल, 1992 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के मात्राएँ, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऐसे प्रशासन से संबंधित अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर ऊपराने वास्तविक व्यय मही समायोजन के अधीन रहते हुए हैं;

(2) 1 अप्रैल, 1992 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, किसी राज्य को ऊपराने (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1990 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसार में उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

(शंकर दयाल शर्मा)

--राष्ट्रपति

[फा. मं. 19'(1)/93-वि.-1]

के. एल. मोहनपुरिया, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

G.S.R. 349(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 152"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

ORDER, 1993

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

- This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1993.
- The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3.(1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1992, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (11) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature on programmes for upgradation of standards and "Special Problems" relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns :—

TABLE

For upgradation of standards relating to

State	Police	Education	Jail	Tribal	Health	Judicial	District and Revenue	Treasury and Accounts	Training	Special Problems
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(Rupees in lakhs)										
Andhra Pradesh	1.61	..	4.26	..	2.03	..	0.41
Assam	..	35.43	8.80	(—)6.38	..
Bihar	1554.68
Himachal Pradesh	2.14	..	1.34	0.98	21.98
Kerala	0.07
Madhya Pradesh	526.50
Orissa	3.33
Punjab	2171.91
Sikkim	0.10
Tripura	(—)0.42	0.42
West Bengal	..	476.15	194.66

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government :

Provided further that the amount of grant specified above against any administration is subject to adjustment within the financial year commencing on the 1st day of April, 1993 against the actual expenditure incurred on approved programme or programmes relating to such administration, as revealed in the accounts of that year.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State in the financial year commencing on the 1st day of April, 1992 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 the Constitution (Distribution of Revenue) No. 3 Order, 1990.

(SHANKAR DAYAL SHARMA)
President

[F. No. 19(1)/93-LI]
K.L. MOHANPURIA, Secy.

